

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

## छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2019 — माघ 12, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 1 फरवरी 2019

आदेश

01/2019 - राज्य कर

क्रमांक एफ-10-05/2019/वाक/पांच(08). - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) यह उपबंधित करती है कि ---

- (i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में लगा है, उक्त उपधारा के अधीन स्कीम का चयन कर सकेगा;
- (ii) ऐसा व्यक्ति जो उक्त स्कीम का चयन करता है, वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य या संघराज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत से अनधिक मूल्य या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की सेवाओं (उनसे भिन्न, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट) की पूर्ति कर सकेगा;
- और, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपधारा (1) के अधीन चयन का पात्र होगा, यदि उक्त उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;

और, कारबार पद्धति की बचत और निवेश के भाग के रूप में सेवाएं प्रदान करना जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है परिणामस्वरूप उपरोक्त स्कीम के लिए उनकी अपात्रता से लघु कारोबारों को अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होती है और इसके कारण उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ।

अतः अब, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश सं. 1/2017-राज्य कर, क्रमांक एफ-10-82/2017/वाक/पांच(149), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 455 तारीख 25 अक्टूबर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 है ।
2. कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा --

- (i) धारा 10 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;
- (ii) कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारावर्त की गणना करने में ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 1 फरवरी 2019

क्रमांक एफ-10-05/2019/वाक/पांच(08).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ 10-05/2019/वाक/पांच(08), दिनांक 01-02-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 1st February 2019

ORDER  
1/2019 – State Tax

No. F-10-05/2019/CT/V(08).- WHEREAS, sub-section (1) of section 10 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that-

- (i) a registered person engaged in the supply of services, other than supply of service referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act, may opt for the scheme under the said sub-section;
- (ii) a person who opts for the said scheme may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act), of value not exceeding ten per cent. of turnover in a State or Union territory in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher;

AND WHEREAS, clause (a) of sub-section (2) of section 10 of the said Act provides that the registered person shall be eligible to opt under sub-section (1), if, save as otherwise provided in sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;

AND WHEREAS, rendering of services as part of the savings and investment practice of business, by way of extending deposits, loans or advances, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, is resulting in their ineligibility for the aforesaid scheme, causing hardships to a lot of small businesses and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of section 10;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 and in supersession of the State Government, in the Commercial Tax Department, Order No. 1/2017-State Tax No. F-10-82/2017/CT/V(149), dated the 13th October, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 455, dated the 25th October, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely: —

1. Short title. —This Order may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account -
  - (i) for determining the eligibility for composition scheme under second proviso to sub-section (1) of section 10;
  - (ii) in computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.